RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 083
दि. 25.12.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

मराठी अस्मिता की सियासत में नया मोड़, खोई जमीन वापस पाने के लिए ठाकरे बंधुओं की ऐतिहासिक एकजुटता

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में दो दशकों बाद एक ऐसा दृश्य सामने आया है, जिसने सियासी हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। बिखराव, घटती जनाधार और लगातार कमजोर होती राजनीतिक पकड़ के दौर से गुजर रहे ठाकरे बंधुओं ने आखिरकार साथ आने का फैसला कर लिया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन ने न सिर्फ मराठी राजनीति में भावनात्मक संदेश दिया है, बल्कि आने वाले मुंबई समेत राज्य की महा नगरपालिकाओं के चुनावों को भी बेहद दिलचस्प बना दिया है। यह गठबंधन केवल दलों का नहीं, बल्कि उस पारिवारिक विरासत का भी प्रतीक है, जिसे बाल ठाकरे ने दशकों तक मराठी अस्मिता के केंद्र में रखा था।

मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक ठाकरे नाम एक ताकत रहा है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में शिवसेना का विभाजन, सत्ता से दूरी और संगठनात्मक कमजोरियों ने इस ताकत को बिखेर दिया। दूसरी ओर राज ठाकरे की मनसे भी अलग पहचान के बावजूद व्यापक राजनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में दोनों नेताओं के लिए यह साफ हो चुका था कि अलग-अलग रास्तों पर चलते हुए राजनीतिक जमीन वापस पाना मुश्किल है। इसी पृष्ठभूमि में यह एकजुटता सामने आई है, जिसे कई लोग मजबूरी का गठबंधन तो कई लोग मराठी राजनीति के पुनर्जागरण की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।

मुंबई समेत राज्य की महा नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए दोनों दलों का एक साथ आना केवल चुनावी तालमेल भर नहीं है। इस मौके पर दोनों परिवारों का एक मंच पर आना, पत्नियों और बेटों की मौजूदगी, उस दूरी को पाटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो सालों से ठाकरे परिवार के भीतर दिखती रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दृश्य कार्यकर्ताओं और मराठी मतदाताओं के लिए भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावी हो सकता है, क्योंकि बाल ठाकरे की विरासत आज भी शिवसेना और मनसे दोनों के समर्थकों के लिए एक साझा स्मृति है।

हालांकि इस एकजुटता की सीमाएं भी उतनी ही स्पष्ट हैं। कांग्रेस के साथ न आने से महाविकास आघाड़ी की पूरी ताकत इस गठबंधन के पीछे नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह गठबंधन अकेले भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट)-राकांपा की महायुति को चुनौती दे पाएगा। भाजपा फिलहाल सार्वजनिक रूप से इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन सियासी गलियारों में यह माना जा रहा है कि अगर यह एकजुटता लंबी चली और मराठी वोटों का एकीकरण हुआ, तो भविष्य में भाजपा को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।

इस बीच शिंदे गुट और भाजपा की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाकरे बंधुओं के साथ आने को स्वार्थ से प्रेरित बताया और कहा कि लोकतंत्र में गठबंधन करना सबका अधिकार है, लेकिन यह गठबंधन केवल सत्ता और राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए किया गया है। शिंदे ने अपने महायुति गठबंधन को विचार और विकास पर आधारित बताते हुए दावा किया कि जनता ऐसे अवसरवादी गठबंधनों को गंभीरता से नहीं लेगी। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस एकजुटता को हल्के में लेते हुए कहा कि इसका कोई बड़ा राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार ठाकरे बंधुओं का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार और स्वार्थ से जुड़ा रहा है और जनता महायुति सरकार के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को देखकर ही फैसला करेगी।

दूसरी ओर ठाकरे बंधुओं की ओर से दिए गए बयान इस गठबंधन के पीछे की रणनीति और भावनात्मक अपील को साफ तौर पर सामने रखते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि आपसी विवादों से बड़ा महाराष्ट्र है और आज की बैठक के बाद अन्य नगर निगमों को लेकर भी घोषणाएं की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि मुंबई का मेयर मराठी होगा और उनकी ही राजनीति से होगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने मराठी समाज से सीधी अपील करते हुए कहा कि पिछली विधानसभा चुनावों में 'बंटेंगे तो कटेंगे' जैसे नारों के जरिए दुष्प्रचार किया गया और अब अगर मराठी समाज फिर से बंटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने इसे मराठी अस्मिता और विरासत को बचाने की आखिरी लड़ाई के रूप में पेश किया।

राजनीतिक मायनों में इस एकजुटता का सबसे बड़ा असर मराठी वोटों पर पड़ सकता है। अब तक शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के अलग-अलग रहने से मराठी मतदाता बंटता रहा, जिसका फायदा भाजपा और अन्य दलों को मिला। दोनों के साथ आने से यह वोट बैंक एकजुट हो सकता है, खासकर मध्य मुंबई और मराठी बहुल इलाकों में। इससे शिंदे गुट पर भी दबाव बढ़ेगा, जो खुद को 'असली शिवसेना' बताता है। ठाकरे बंधुओं की एकजुटता से उस दावे की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते हैं और कैडर के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है।

बीएमसी पर नियंत्रण की लड़ाई इस गठबंधन की असली परीक्षा होगी। देश की सबसे अमीर नगर निगम पर लंबे समय तक शिवसेना का दबदबा रहा है, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद उद्धव ठाकरे की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई। अब राज ठाकरे के साथ आने से उन्हें खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका मिल सकता है। हालांकि यह मौका अवसर में बदलेगा या नहीं, इसका फैसला जनता और चुनावी नतीजे ही करेंगे।

कुल मिलाकर ठाकरे बंधुओं की यह एकजुटता महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता, पारिवारिक विरासत और बदलते राजनीतिक यथार्थ का संगम है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि यह मनोमिलन अस्थायी चुनावी समझौता साबित होता है या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में एक स्थायी बदलाव की नींव रखता है।

पुलिस पहरे में बड़ी चूक, मेडिकल कॉलेज से फरार हुआ इनामी अपराधी, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

(जीएनएस)। प्रतापगढ़। जिले में कानून-व्यवस्था और पुलिस अभिरक्षा की गंभीर खामियां उस वक्त उजागर हो गईं, जब 25 हजार रुपये का इनामी अपराधी पुलिस की कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया। यह घटना न सिर्फ पुलिस महकमे के लिए शर्मनाक साबित हुई, बल्कि आम जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता भी पैदा कर गई। जिस आरोपी को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया था, उसी का अस्पताल से फरार हो जाना कई सवाल खड़े करता है—क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों में सख्त है, या फिर जमीनी स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है? पूरा मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उड़ैयाडीह बाजार से जुड़ा है, जहां सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित आरोपी जावेद लंबे समय से पुलिस

की तलाश में था। आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी बड़ी चुनौती बनी हुई थी। मंगलवार देर रात पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से जावेद घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बताया गया कि आरोपी की हालत को देखते हुए उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया था और उसके पहरे के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

लेकिन बुधवार तड़के करीब चार बजे ऐसा कुछ हुआ, जिसने पूरी पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कथित लापरवाही का फायदा उठाकर आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। यह खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जिस अपराधी को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा था, उसका यूं भाग निकलना न केवल सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है, बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि आरोपी को भगाने में कहीं किसी की मिलीभगत तो नहीं थी। हालांकि, इस पहलू पर जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन शुरुआती घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए बिना देरी के सख्त कदम उठाए। उन्होंने घना चौकी प्रभारी कमलेश कुमार समेत चार पुलिसकर्मियों—आरक्षी अशोक कुमार, विनोद सिंह और गुलशन कुमार—को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस अभिरक्षा में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि जांच में किसी भी स्तर पर मिलीभगत या गंभीर चूक पाई गई, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में भर्ती किसी भी आरोपी की सुरक्षा एक संवेदनशील जिम्मेदारी होती है, खासकर तब, जब वह गंभीर अपराधों में वांछित और इनामी हो।

राजमार्गों पर मवेशियों का खात्मा, एक कॉल पर पहुंचेगी रेस्क्यू टीम, हादसों पर लगेगा ब्रेक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों और लावारिस पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब ठोस और सख्त कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों को मवेशियों से मुक्त करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत अब आम नागरिक की सिर्फ एक कॉल पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचेगी और राजमार्ग से पशुओं को सुरक्षित तरीके से हटाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हजारों हादसों और जानमाल के नुकसान में बड़ी कमी आएगी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हर साल राष्ट्रीय राजमार्गों पर मवेशियों की मौजूदगी के कारण औसतन करीब 10 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग चार हजार लोगों की जान चली जाती है। इन हादसों में बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन सवार शामिल होते हैं, जो अचानक सामने आए पशुओं की वजह से वाहन से नियंत्रण खो बैठते हैं। खासकर रात के समय और कोहरे या कम रोशनी में मवेशी जानलेवा साबित हो रहे हैं। इन्हीं गंभीर हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने को कहा था।

नए एक्शन प्लान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है, जिसमें तकनीक, निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और आम जनता की भागीदारी को एक साथ जोड़ा गया है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात रूट पेट्रोल वाहन चौबीसों घंटे गश्त करेंगे। इन वाहनों में डैशबोर्ड कैमरे अनिवार्य किए गए हैं ताकि हर गतिविधि रिकॉर्ड हो सके और किसी भी लापरवाही की जवाबदेही तय की जा सके। इसके साथ ही एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर राजमार्गों पर मवेशियों की पहचान की जाएगी और उनकी लोकेशन को तुरंत ट्रैक किया जाएगा।

इस पूरी व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी आम जनता है। सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 को इस योजना का केंद्र बिंदु बनाया है। कोई भी नागरिक अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मवेशी या लावारिस पशु देखता है, तो वह इस नंबर पर कॉल कर सकता है। कॉल मिलते ही संबंधित क्षेत्र की रेस्क्यू टीम को अलर्ट भेजा जाएगा और टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी। सरकार का दावा है कि यह प्रतिक्रिया समय बेहद कम रखा जाएगा ताकि पशुओं को हटाने में देरी न हो और हादसे की आशंका को टाला जा सके। रेस्क्यू के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता न हो। एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि बिना बल प्रयोग किए पशुओं को सड़क के किनारे या सुरक्षित होल्डिंग एरिया तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय पुलिस, नगर निकाय और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा। पशुओं को अस्थायी या स्थायी आश्रय स्थलों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तय की गई है, ताकि वे दोबारा राजमार्ग पर न लौट सकें।

सरकार ने यह भी माना है कि कुछ खास स्थान ऐसे हैं जहां मवेशियों की समस्या ज्यादा गंभीर है। इन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, फेंसिंग, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और चेतावनी संकेत लगाए जाएंगे। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में 100 से 150 मीटर पहले चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड पर ड्राइवरों को 'सावधान, आगे पशु हैं' जैसे संदेश दिखाए जाएंगे। इसके साथ ही रिफ्लेक्टिव बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रात के समय वाहन चालकों को दूर से ही सतर्क किया जा सके। यह योजना केवल तकनीकी उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक जवाबदेही भी तय की गई है। हर घटना को जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ दर्ज किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में बार-बार समस्या आ रही है। इसके आधार पर संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। एनएचएआई का मानना है कि इस डेटा आधारित निगरानी से न सिर्फ हादसों में कमी आएगी, बल्कि लंबे समय में समस्या का स्थायी समाधान भी संभव होगा।

भारतीय आसमान में प्रतिस्पर्धा की नई उड़ान, नई एयरलाइनों को सरकार की हरी झंडी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय विमानन क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे एकतरफा वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम और दूरगामी फैसला लिया है। इंडिगो में हालिया परिचालन संकट और यात्रियों की लगातार बढ़ती शिकायतों के बीच सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारतीय आसमान केवल गिनी-चुनी कंपनियों का अखाड़ा नहीं रहेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर विकल्प देने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दो नई एयरलाइनों अल-हिंद एयर और फ्लाईएक्सप्रेस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की शंख एयर भी 2026 में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है, जिसे पहले ही एनओसी मिल चुकी है। इस फैसले को भारतीय विमानन बाजार के लिए एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन बाजार तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस वृद्धि का लाभ सीमित कंपनियों तक सिमट कर रह गया। टाटा समूह की एअर इंडिया और इंडिगो ने मिलकर घरेलू बाजार के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। डीजीसीए के आंकड़े बताते हैं कि अकेले इंडिगो की हिस्सेदारी करीब 65 प्रतिशत है, जो किसी भी बाजार के लिए गंभीर असंतुलन का संकेत है। इस 'डुओपोली' की स्थिति में यात्रियों के पास विकल्प सीमित हो गए, किरायों में मनमानी बढ़ोतरी देखने को मिली और सेवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे। सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह वर्चस्व न सिर्फ यात्रियों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि पूरे विमानन क्षेत्र को जोखिम में डाल देगा। हाल ही में इंडिगो में आई तकनीकी खराबियों और परिचालन बाधाओं ने इस खतरे को और उजागर कर दिया।

आखिरकार अरावली पर जागी सरकार, गुजरात से दिल्ली तक खनन के नए पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वर्षों से पर्यावरणविदों और अदालतों की चेतावनियों के बावजूद उपेक्षित रही अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र सरकार आखिरकार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े एक अहम फैसले में केंद्र सरकार ने गुजरात से लेकर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली संपूर्ण अरावली रेंज में खनन के लिए नए पट्टे देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जा सकेगी। केंद्र सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के बाद लिया गया है। बीते नवंबर में शीर्ष अदालत ने अरावली क्षेत्र में हो रहे खनन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा था कि जब तक एक समग्र और वैज्ञानिक प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक नए खनन पट्टे नहीं दिए जाने चाहिए। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को पहले भी आगाह किया था, लेकिन अब 24 दिसंबर को जारी निर्देशों में इसे और अधिक स्पष्ट और सख्त कर दिया गया है। सरकार ने साफ कहा है कि यह प्रतिबंध केवल किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा, बल्कि गुजरात से लेकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैली पूरी अरावली पर्वतमाला पर समान रूप से लागू रहेगा। मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अरावली की अखंडता को बनाए रखना और इसे एक सतत भूवैज्ञानिक शृंखला के रूप में संरक्षित करना है। अरावली न केवल देश की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, बल्कि यह उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन, भूजल स्तर और जैव-विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरकार ने अपने निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया

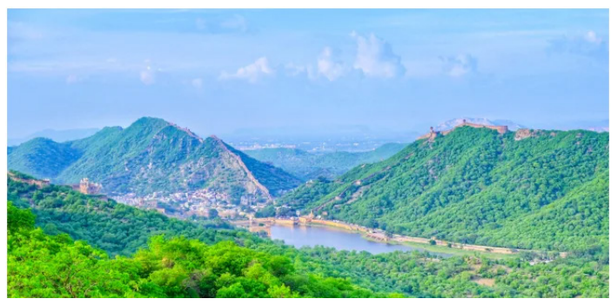

है कि जब तक सतत खनन प्रबंधन योजना यानी एमपीएसएम को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार की नई खनन लीज नहीं दी जा सकती। इस योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी आईसीएफआरई को सौंपी गई है। मंत्रालय ने आईसीएफआरई से कहा है कि वह पूरे अरावली क्षेत्र का व्यापक अध्ययन करे और ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करे, जहां खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। यह पहचान उन इलाकों के अतिरिक्त होगी, जहां पहले से ही खनन पर प्रतिबंध लागू है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, आईसीएफआरई को एक समग्र और विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी, जिसमें पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और क्षेत्र की वहन क्षमता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव लिए जा सकें। इसके तहत यह भी आकलन किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में पारिस्थितिक क्षति सबसे अधिक हुई है और वहां बहाली या पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि इस पहल से पूरे अरावली क्षेत्र में संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा और अधिक व्यापक होगा। इसमें स्थानीय भूगोल, वनस्पति, वन्यजीव और जैव-विविधता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि अनियमित और अवैध खनन के कारण अरावली का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे जल संकट, वायु प्रदूषण और जलवायु असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से चल रही खदानों को लेकर तत्काल कोई स्वतः बंदी का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन उनके लिए नियमों को और सख्त कर दिया गया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे मौजूदा खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें, सभी पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन कराएं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण से कोई समझौता न हो।

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का यह फैसला अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की दिशा में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। वर्षों से पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रही इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के लिए यह कदम राहत भरा है, हालांकि इसका वास्तविक असर तभी दिखेगा जब राज्यों द्वारा इन निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा और अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी।

संपादकीय

सरकारी सख्ती से बंद होगा मारक खेल

शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब कोई बुजुर्ग या आम लोग साइबर ठगी के शिकार न हुए हों। पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक सेवानिवृत्त जज भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार हो गए। पिछले सप्ताह ऐसा ही एक अन्य दुखद मामला पुणे से सामने आया जब साइबरों ठगों ने एक 82 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल हाउस अरेस्ट स्कैम में फंसाकर 1.19 करोड़ लूट लिए। कई दिन के मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक क्षति से टूट गए वृद्ध की आखिर सदमे से मौत हो गई। यह विचारणीय पहलू है कि कैसे पढ़े-लिखे लोग साइबर ठगों की साजिश की गिरफ्त में आ जाते हैं। वैसे आम आदमी को साइबर ठगों व फर्जी फोन कॉल्स से बचाने के लिये पुख्ता व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। आम लोगों की सुविधा व सुरक्षा के लिये सरकार के प्रयासों के बाद अब दूरसंचार विभाग ने मार्च 2026 में ऐसी व्यवस्था लागू करने के तैयारी की, जिसमें बिना ट्रू-कॉलर के खुद मोबाइल अवांछित फोन के प्रति सजग करेगा। नियामक संस्था ट्राई ने इस प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। यह विडंबना ही कि जैसे-जैसे नई तकनीक आम आदमी के जीवन में सुविधा लाती है, वहीं असामाजिक तत्व उसे लूट-खसोट का हथियार बनाने में आगे निकल जाते हैं। देश में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार और मोबाइल फोन की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ ही साइबर अपराधों में खासी तेजी आई है। जरा सी चूक होने पर लाखों लोग, साइबर धोखाधड़ी में अपने जीवनभर की पूंजी कुछ ही क्षणों में गवां देते हैं। अपराधियों का संजाल इतना विस्तृत व रहस्यमय है कि प्रवर्तन एजेंसियां जब तक उन तक पहुंचती हैं, पैसा विदेशों में ट्रांसफर हो जाता है। इस संकट का एक पहलू अनजान नंबरों से आने वाली फोन कॉल्स होती हैं, जिसके जरिये अपराधी लोगों को भ्रमित कर जीवन की जमा पूंजी लूट लेते हैं। दरअसल, संचार क्रांति के चलते तमाम सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हुई हैं, लेकिन इस सुविधा के साथ पुरानी पीढ़ी साम्य नहीं बैठा पाती है।

अब इसी चुनौती को दूर करने के लिये दूरसंचार विभाग आम उपभोक्ता को ऐसी सुविधा देने जा रहा है, जिसमें फोन करने वाले को पहचाना जा सकेगा। फोन पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा नजर आएगा। फिर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार फोन कॉल्स लेना तय कर सकता है। दूरसंचार नियामक ट्राई की मंजूरी के बाद इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हालांकि, फोन करने वाले व्यक्ति की जानकारी जुटाने के कई ऐप अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग कुछ ही लोग कर पाते हैं। वैसे ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐप द्वारा दी जाने वाली सूचना सटीक है। ऐसे में यदि दूरसंचार विभाग की कोशिश सिरे चढ़ती है तो इससे करोड़ों उपभोक्ताओं को सुरक्षा कवच मिल पाएगा। पहले इस सुविधा का लेना मांग पर आधारित था, लेकिन बाद में तय किया गया कि यह सुविधा प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। विश्वास किया जा रहा है कि अगले साल मार्च तक पूरे देश में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस सुविधा से किसी सीमा तक मोबाइल के जरिये धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। मोबाइल उपयोगकर्ता की सजगता इसमें मददगार हो सकेगी। स्क्रीन पर अनजान नंबर व नाम देखने के बाद मोबाइलधारक फोन कॉल्स को उठाने से बच सकता है। वैसे इसके साथ ही देश में डिजिटल साक्षरता की दिशा में व्यापक पहल करने की जरूरत है। विभिन्न सूचना माध्यमों के जरिये लोगों को सजग-सतर्क किए जाने की आवश्यकता है। शहरों से लेकर ग्राम पंचायतों तक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को बताया जाना चाहिए कि बैंक, सीबीआई, कोर्ट या अन्य प्रवर्तन एजेंसियां कभी फोन करके उनके बैंक खाते या अन्य मामलों की जानकारी नहीं मांगती हैं। ऐसे फर्जी कॉल्स की प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिये हेल्पलाइन सुविधाओं में विस्तार करने की भी जरूरत है। देश में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को भी बाध्य किया जाना चाहिए कि वे उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करके संदिग्ध फोन नंबरों के प्रति सचेत करें।

सुशासन के अटल पथ पर अग्रसर छत्तीसगढ़

"सौभाग्य से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता अपने राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल जी के पुण्य कृतित्व के लिए उन्हें अपनी आदरांजलि प्रकट कर रही है। माननीय अटल जी राजनीति को परमार्थ का माध्यम मानते थे।

भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में विकास और सुशासन के प्रतीक हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की जिस यात्रा की ओर अग्रसर है, उसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया सुशासन का वह मंत्र पाथेय है, जिसे केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकारों ने अंत्योदय की रीति-नीति बनाया है। भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कवि हृदय अटल जी छत्तीसगढ़ से गहरा नाता था। छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले रायपुर के सप्रे मैदान में आयोजित चुनावी सभा का दृश्य आज भी मुझे याद है, जब अटल जी की एक झलक पाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से लोग वहां पहुंचे थे। उस समय उन्होंने जैसे ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का उद्घोष लगाया पूरा मैदान छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति आस्था के भाव से स्पंदित हो उठा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप 11 सीट जीतकर दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। उस चुनाव में हमारी पार्टी के सात सांसद छत्तीसगढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़वासियों से किया गया वादा पूरा कर अपनी संकल्पबद्धता को प्रमाणित कर राजनीतिक प्रतिबद्धता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा और 9 अगस्त को राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव पर मुहर लगी। चार सितम्बर 2000 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन के बाद एक नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य देश के 26 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। सौभाग्य से यह वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता अपने राज्य निर्माता श्रद्धेय अटल जी के पुण्य कृतित्व के लिए उन्हें अपनी आदरांजलि प्रकट कर रही है। माननीय अटल जी राजनीति को परमार्थ का माध्यम

मानते थे। वह समावेशी विकास के अगुवा थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए उन्होंने देशभर के गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा। आज अटल जी के विजन पर देशभर में 6 लाख किलोमीटर से अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बन चुकी हैं। अटल जी की दूरदृष्टि को साकार करती यह महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में समृद्धि की वाहक बनी है। इसका आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले 25 वर्ष में लगभग 22 हजार 750 किमी लम्बी सड़कों का जाल बिछा जा चुका है। अटल जी को देश में राजमार्ग क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। अटल जी के प्रधानमंत्रीत्व काल में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए देश को एकसूत्र में पिरोती है। 11-13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी संप्रभुता एवं अखंडता से कोई समझौता नहीं कर सकता।

अटल जी का पूरा जीवन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित रहा। उन्होंने केन्द्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की, जिससे जनजातीय समाज के सर्वांगीण उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना जैसी नीतिगत पहल से छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी जनजातीय बाहुल्य राज्य लाभान्वित हो रहे हैं।

अटल जी ने स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2001-2002 में सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया। इसकी बदौलत देश के हर आय वर्ग के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की राह आसान हुईं। अटलजी ने विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को देश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम शुरू किया। अटल जी के कार्यकाल में भारत ने करगिल युद्ध में न सिर्फ विजय प्राप्त की बल्कि आतंकवाद पोषक पाकिस्तान के दांत खट्टे करते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग-थलग करने का काम किया।

भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के आचरण और उसकी प्राथमिकता तथा हमारी सरकार के नीतिगत निर्णयों में श्रद्धेय अटल जी के चिंतन की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। अटल जी की जिस प्रेरणा और दर्शन को आत्मसात कर हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों पर जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो स्वप्न देखा था उसे जनता के आशीर्वाद से डॉ रमन सिंह जी के नेतृत्व में पंद्रह वर्ष तक भाजपा सरकार ने साकार रूप देने का कार्य किया, विकास की उसी अटल दृष्टि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं श्री विष्णु देव साय जी की अगुआई वाली वर्तमान भाजपा सरकार अंत्योदय के अनुष्ठान में जुटी है। छत्तीसगढ़ में हमारी डबल इंजन की सरकार के लिए पहले दिन से ही गरीब, किसान, महिला, युवा, जनजातीय समाज का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। हमारी सरकार ने गठन के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय लिया। आज प्रदेश में 26 लाख पीएम आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने किसानों के साथ जिस तरह छल किया, उससे वह अन्नदाता की नजरों से हमेशा के लिए उतर गई है। हमारी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पिछले तीन खरीफ सीजन से हमारी सरकार किसानों से 3100 प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी के कीर्तिमान रच रही है।

छत्तीसगढ़ देश की इकोनॉमी का इंजन है। बावजूद इसके नक्सलवाद ने हमारी विकास यात्रा को काफी बाधित किया था। अब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प तथा जवानों के अदम्य साहस से माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के करीब है। नक्सलवाद के उन्नमूलन में नियद नेल्ला नार समेत डबल इंजन सरकार की सुशासनकारी योजनाएं वरदान बनी हैं।

श्रद्धेय अटल जी ने हमेशा शासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को प्राथमिकता दी। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की सुशासन पहल को प्रभावी रूप दिया जा रहा है। जनता के हित के लिए बनने वाली योजनाओं का लाभ उसके वास्तवीक हितग्राहियों को मिले इसके लिए हमारी सरकार ने अटल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। इसके जरिए राज्य में योजनाओं की निगरानी की जाती है। इसी तरह ई-ऑफिस, सिंगल विंडो सिस्टम-2.0, सुगम एवं संगवारी एप सुशासन के अटल मंत्र को साकार रहे हैं। बदलती जीवनशैली के साथ सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं ने जीवन को सुगमता प्रदान करने के साथ शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने का भी काम किया है। कांग्रेस की सरकार ने जहां कोयले के परिवहन में परमिट की व्यवस्था को ऑफलाइन कर दिया था वहीं हमारी सरकार ने इसे ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। पीएससी जैसी परीक्षा को कांग्रेस सरकार ने दागदार कर युवाओं के सपनों का कत्ल किया लेकिन हमारी सरकार ने इसकी पारदर्शिता और प्रमाणिकता को बढ़ाया है। युवाओं की सुविधा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने इस वर्ष अटल जी की जयंती पर अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। ऐसे में यह सुशासन दिवस नये संकल्पों के साथ प्रदेश और देश की तरक्की को गति देने का है। हम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ को गढ़ने जुटे हैं।

प्रेरणा

भीतर की शांति की तलाश

प्राचीन यूनान की धरती पर एक ऐसा व्यक्ति रहता था, जिसे न तो वैभव ने आकर्षित किया और न ही समाज की स्वीकृति की चिंता थी। उसका नाम डायोजनीज था। वह भव्य भवनों और सोने-चांदी से सजे जीवन को छोड़कर एक साधारण से घड़े में रहना पसंद करता था। उसके वस्त्र साधारण थे, भोजन सीमित था और दिनचर्या में कोई दिखावा नहीं था। नगर के लोग उसे अजीब दृष्टि से देखते थे। कुछ उसे पागल कहते, कुछ दार्शनिक और कुछ ऐसा व्यक्ति मानते थे, जो जीवन की वास्तविकताओं से भाग गया है। लेकिन डायोजनीज का मानना था कि जो व्यक्ति बाहरी दिखावे से मुक्त हो जाता है, वही जीवन के सत्य को समझ पाता है। उसके लिए जीवन संग्रह का नाम नहीं था, बल्कि समझ का मार्ग था।

एक दिन नगर में चहल-पहल थी। अमीर व्यापारियों और राजपरिवार से जुड़े लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई थी। उसी भीड़ में से एक युवक निकला, जिसके वस्त्र रेशमी थे, अंगुलियों में कीमती अंगूठियां चमक रही थीं और साथ में सेवक भी थे। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह कई दिनों से मन की अशांति से जूझ रहा था। उसके पास धन था, शक्ति थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी, लेकिन फिर भी मन किसी अज्ञात खालीपन से भरा हुआ था। लोगों की प्रशंसा उसे क्षणिक सुख देती थी, जो कुछ ही देर में फीकी पड़ जाती थी। उसने डायोजनीज के बारे में सुना था कि वह जीवन के रहस्य समझाता है, इसलिए वह उसके पास आया। युवक ने आदर के साथ अपनी व्यथा रखी। उसने कहा कि जितना वह पाता है, उतना ही और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। एक लक्ष्य पूरा होता है, तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। वह दिन-रात इसी दौड़ में लगा रहता है, लेकिन मन शांत नहीं होता। उसकी बात सुनकर डायोजनीज ने कोई तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह उठा और युवक को अपने साथ चलने का संकेत किया। दोनों नगर की सीमा से बाहर एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां धूप और छांव एक-दूसरे से सटी हुई थीं। वहीं एक कुत्ता बैठा था। वह कुछ देर धूप में बैठा, फिर उठकर छांव में चला गया और वहां आराम से लेट गया। डायोजनीज ने युवक से पूछा कि यह कुत्ता क्या कर रहा है। युवक ने उत्तर दिया कि वह आराम खोज रहा है, जहां उसे अच्छा लग रहा है, वहां चला गया। तब डायोजनीज ने गंभीर स्वर में पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। यह प्रश्न युवक के मन में गूंजने लगा। उसे पहली बार लगा कि वह सचमुच यह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। वह बस आदतों, अपेक्षाओं और समाज की दौड़ में बहता चला जा रहा है। डायोजनीज ने कहा कि इस कुत्ते को देखो, यह अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। धूप में असुविधा हुई तो छांव में चला गया। न उसे महल चाहिए, न प्रशंसा, न भविष्य की चिंता। उसकी आवश्यकता सीमित है, इसलिए उसका मन भी शांत है। मनुष्य की समस्या यह नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि यह है कि उसकी इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाओं की यह अनंत श्रृंखला मनुष्य को कभी चैन से बैठने नहीं देती। वह जितना पाता है, उतना ही खाली महसूस करता है, क्योंकि वह अपने भीतर की रिक्तता को बाहर की चीजों से भरना चाहता है।

युवक ने तर्क दिया कि बिना धन और प्रतिष्ठा के समाज में कोई मूल्य नहीं होता। डायोजनीज मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि समाज का मूल्यांकन अक्सर भ्रमित होता है। यहां व्यक्ति को उसके पास मौजूद वस्तुओं से आंका जाता है, उसके विचारों और मन की शांति से नहीं। लेकिन जिसने भीतर की शांति पा ली, उसे समाज की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं के साथ सहज हो जाता है। उसे न किसी से ईर्ष्या होती है और न ही किसी से भय। डायोजनीज ने अपने घड़े की ओर संकेत किया और बताया कि यही उसका घर है। न दरवाजे, न ताले, न पहरेदार। उसे डर नहीं कि कोई उससे कुछ छीन लेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन को ही इतना हल्का बना लिया है कि छीनने जैसा कुछ बचा ही नहीं। उसने बताया कि पहले उसके पास एक कटोरा था, लेकिन जब उसने एक बच्चे को हाथ से पानी पीते देखा, तो उसे लगा कि कटोरा भी अनावश्यक है। उसी क्षण उसने उसे भी त्याग दिया। उसके लिए त्याग का अर्थ कष्ट नहीं था, बल्कि अनावश्यक बोझ से मुक्ति था।

युवक के मन में यह बातें धीरे-धीरे उतरने लगीं। उसे अपने जीवन की व्यस्तता याद आई, जहां हर क्षण किसी न किसी उपलब्धि की चिंता रहती थी। उसे यह भी याद आया कि कितनी ही बार उसने खुशी को किसी वस्तु या पद से जोड़ा और हर बार निराश हुआ। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, बल्कि उसकी सोच में है। उसने डायोजनीज से पूछा कि फिर वास्तविक सुख क्या है। डायोजनीज ने कहा कि सुख कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह तब आता है, जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है और अपनी इच्छाओं को समझ लेता है। उस दिन युवक देर तक डायोजनीज के साथ बैठा रहा। सूर्य ढलता रहा और आकाश के रंग बदलते रहे। युवक के भीतर भी कुछ बदल रहा था। उसने जाना कि सादगी का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि स्पष्टता है। संतोष का अर्थ ठहराव नहीं, बल्कि सही दिशा में चलना है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, वह निष्क्रिय नहीं हो जाता, बल्कि वह बिना बेचैनी के कर्म करता है। कहा जाता है कि उस मुलाकात के बाद युवक का जीवन धीरे-धीरे बदलने लगा। उसने धन और कार्य को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना छोड़ दिया। उसने समय निकालकर स्वयं के साथ रहना शुरू किया। उसने पाया कि जब अपेक्षाएं कम होती हैं, तो रिश्ते सरल हो जाते हैं। जब तुलना समाप्त होती है, तो मन हल्का हो जाता है। उसे यह समझ में आने लगा कि भीतर की शांति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन से आती है। डायोजनीज अपने स्थान पर बने रहे। लोग आते-जाते रहे। कुछ हंसते, कुछ सीखते, कुछ असहज होकर लौट जाते। लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से यह संदेश मिलता था कि जीवन का अर्थ संग्रह नहीं, बल्कि बोध है। उन्होंने बिना किसी ग्रंथ के, बिना किसी उपदेश के यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। भीतर की शांति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साहस है—स्वयं को जानने का साहस, इच्छाओं को देखने का साहस और उन्हें नियंत्रित करने का साहस।

बुनियादी बदलाव से बचती कांग्रेस

अभी हाल में दो तस्वीरें आईं, जो काफी चर्चा में रहीं। एक में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत पक्ष-विपक्ष के कई नेताओं के साथ मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की ले रही हैं। दूसरी तस्वीर उसके एक दिन पहले आई, जिसमें प्रियंका सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हिमाचल की सड़कों को लेकर और केरल में अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा कर रही हैं। वैसे तो संसदीय परंपरा में ये सामान्य घटनाएं हैं, लेकिन इसका संदेश गूंजता है। विपक्ष सलाह दे सकता है, शक्ति हो तो दबाव बना सकता है, लेकिन सरकार को अस्वीकार नहीं कर सकता, जिसकी कोशिश खासतौर से मुख्य विपक्ष की ओर से होती रही है।

इससे शायद ही कोई इन्कार करे कि एक मोड़ पर जाकर नेतृत्व ही अहम हो जाता है। वही पार्टी की दिशाएं तय करने लगता है, उसकी विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता से पार्टी की पहचान होने लगती है। वही पार्टी को हराता और जिताता है और भविष्य तय करने लगता है। वर्ष 2025 इस सवाल का बार-बार जवाब देते दिखा। इस वर्ष दो अहम चुनाव हुए। एक देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरा हमेशा से राजनीति का अखाड़ा बने रहे बिहार में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी नेता विपक्ष तो बने ही, पार्टी के अंदर भी उन्होंने प्रभावी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। इन दोनों राज्यों में चुनाव के बाद फिर से स्पष्ट हो गया कि खुद को अपग्रेड करने की उनकी क्षमता कहीं न कहीं लुप्त है। वे कांग्रेस नेता से खुद को नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपग्रेड नहीं कर सके। कारण है संवाद की कमी, जिद और अकड़।

राहुल विपक्ष के नेताओं से तारतम्य बनाने में असफल रहे हैं। सरकार से संवाद करना उनके लिए असहज है। संसद के अंदर भी उनका सख्त चेहरा ही दिखता है। पार्टी में संवाद की स्थिति क्या है, यह बार-बार पार्टी नेताओं की ओर से ही सोनिया गांधी को लिखी जा रही चिट्ठी से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे में प्रियंका की तस्वीरों ने चर्चा को छेड़ दिया है तो यह असामान्य नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो हर किसी से संवाद में माहिर हैं। विपक्ष के नेताओं के साथ उनके उन्मुक्त संवाद को देखा जा सकता है। वे उन मुद्दों को छूते हैं, जो जनता को स्पर्श करें। चुनाव के वक्त पार्टी के साथ खड़े होते हैं और जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। उनकी ओर से दिखाए जाने वाले इतिहास के कुछ पन्नों से कांग्रेस परेशान जरूर होती है, पर बतौर प्रधानमंत्री उनकी यह जिम्मेदारी भी तो है कि युवाओं को इतिहास याद दिलाएं। सकारात्मक सोचने की अपील करें।

जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था तो लगा था कि कांग्रेस समय और लोगों की अपेक्षा के अनुसार बदलने को तैयार होने लगी है। बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ कि दो दिन के शोर-शराबे के बाद विपक्ष भी चर्चा करने और कार्यवाही को सुचारु करने के लिए राजी हो गया। यह सुखद अहसास था, लेकिन मानसिक रूप से बदलाव नहीं हुआ। चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो सार्थक सुझाव दिए जाने चाहिए थे। बजाय इसके चुनाव आयोग के अधिकार को छीनने की मांग ही होती रही। संविधान भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि एसआइआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि यह हो ही नहीं। जो सवाल किए गए, उसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कमेटी की बात भी आई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सरकार ने एक नियम तय किए, जो सरकार का अधिकार है। सरकार के अधिकार को नकारने का क्या अर्थ? युवाओं को तर्क से समझाना होता है, इतिहास से उदाहरण बताना होता है। तभी वे जुड़ते हैं। युवाओं को तो यही समझ आया कि पहले नेता विपक्ष भी कमेटी में नहीं होते थे। अब मोदी सरकार ने लोकसभा के नेता विपक्ष को शामिल कर दिया। यह नियम किसी भी सरकार पर लागू होगा। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी छवि बड़ी बनानी थी। उन्हें राजनीति में अपराधीकरण रोकने की बात करनी चाहिए थी, एक ही स्थान से चुनाव लड़ने के लिए कानून बनाए जाने का सुझाव देना चाहिए था। एसआइआर पर तो अब चुनाव आयोग ने चुनौती दे दी है और कहा कि कुछ राज्यों में एसआइआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। उसे देख लीजिए और कोई आपत्ति हो तो बताइए। संसद सत्र के दौरान ही सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी बैठक हुई और नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताते हुए सारे नाम खारिज कर दिए कि उसमें सामाजिक न्याय का ख्याल नहीं रखा गया, पर जब सूची आई तो उसमें आठ में पांच नाम वंचित वर्ग से थे। ऐसी फिसलनों से विश्वसनीयता का संकट खड़ा होता है। हाल में एसआइआर को लेकर कांग्रेस की एक बैठक हुई। उसमें चिंता जताई गई कि कांग्रेस के पास बूथ लेवल एजेंट बहुत कम हैं। देश पर छह दशक तक राज करने वाली पार्टी के पास बीएलए न हों तो दोष नेतृत्व का माना जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव आने वाला है और बताते हैं कि तृणमूल के एक नेता ने किसी से कहा कि कांग्रेस की ओर से अगर गठबंधन की बात होगी तो उनसे स्पष्ट कहा जाएगा कि सहयोग कीजिए।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश के अंदर जो भाव था वंदे मातरम् उसकी अभिव्यक्ति थी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 11 वर्षों में देश में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा बुलंद हुई है, लेकिन राहुल गांधी को शायद उस चर्चा में रुचि नहीं थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान जो बात कही, वह तर्कसंगत थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत नेतृत्व के कारण होती है। कांग्रेस में यह बात पहले भी कई शीर्ष नेता कह चुके हैं। राज्यों में भी भाजपा मोदी के नाम की गारंटी लेकर उतरती है। यह सच है कि भाजपा की विश्वसनीयता और लोकप्रियता आज के दिन मोदी के नेतृत्व के कारण है। कुछ राज्यों में अलग-अलग नेताओं ने भी नेतृत्व दिया है और बार-बार जीत भी रहे हैं। कांग्रेस को विश्वसनीयता के संकट से बाहर आना ही होगा।

अभियान

श्रीराम का अदृश्य कवच: भय, संकट और अशांति से मुक्ति की सनातन साधना

सनातन धर्म की परंपरा में भगवान श्रीराम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं हैं, बल्कि वे जीवन जीने की संपूर्ण कला का प्रतीक माने जाते हैं। मर्यादा, सत्य, त्याग, धैर्य और करुणा—इन सभी गुणों का सजीव रूप श्रीराम के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। जब मनुष्य जीवन की कठिन राहों पर चलता है, जब चारों ओर अनिश्चितता, भय और संकट घेर लेते हैं, तब श्रीराम का स्मरण केवल आस्था नहीं रह जाता, बल्कि वह आत्मबल का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। इसी स्मरण को एक सशक्त साधना का रूप देता है रामरक्षा स्तोत्र, जिसे शास्त्रों में एक दिव्य कवच के समान माना गया है।

रामरक्षा स्तोत्र का महत्व केवल इसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके भाव और चेतना में निहित है। यह स्तोत्र भगवान श्रीराम के नाम, उनके अंगों, उनके शौर्य और उनके तेज का ऐसा वर्णन करता है, जो साधक के मन और आत्मा दोनों को सुरक्षित करता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार योद्धा युद्धभूमि में उतरने से पहले कवच धारण करता है, उसी प्रकार जीवन के संघर्षों में उतरने से पहले रामरक्षा स्तोत्र का पाठ मनुष्य को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा केवल बाहरी दुर्घटनाओं या शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर पल रहे भय, असंतोष और नकारात्मकता से भी रक्षा करती है।

रामरक्षा स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा भी इसके महत्व को और गहराई देती है। मान्यता है कि महर्षि बुधकौशिक को यह स्तोत्र भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था। स्वयं शिव ने इसे श्रीराम की रक्षा और महिमा का कवच बताया था। इसीलिए इस स्तोत्र में केवल श्रीराम ही नहीं, बल्कि शिव और हनुमान की ऊर्जा भी समाहित मानी जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसके जीवन में केवल रामकृपा ही नहीं, बल्कि हनुमान जी की निर्भयता और शिव की स्थिरता भी प्रकट होने लगती है।

आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना सशक्त दिखाई देता है, भीतर से उतना ही असुरक्षित और चिंतित होता जा रहा है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, संबंधों की उलझन और जीवन की दौड़ ने मनुष्य को भीतर से थका दिया है। ऐसे समय में रामरक्षा स्तोत्र एक शांत आश्रय की तरह कार्य करता है। जब व्यक्ति रोजाना इसका पाठ करता है, तो उसका मन धीरे-धीरे स्थिर होने लगता है। उसे यह अनुभूति होने लगती है कि हर परिस्थिति उसके वश में नहीं है, लेकिन उसका साहस और आस्था उसके वश में अवश्य है। यही अनुभूति उसे भीतर से मजबूत बनाती है।

कहा जाता है कि रामरक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। भय केवल शारीरिक खतरे का नहीं होता,

बल्कि मानसिक और भावनात्मक भय भी उतना ही घातक होता है। कई बार मनुष्य बिना किसी स्पष्ट कारण के ही आशंकाओं से घिरा रहता है। रामरक्षा स्तोत्र का जाप इन आशंकाओं को धीरे-धीरे शांत करता है। श्रीराम का नाम मन में यह भाव जगाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय ही प्राप्त होती है। यह विश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाने नहीं देता।

रामरक्षा स्तोत्र को एक ऐसा कवच माना गया है, जो साधक के चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बना देता है। इस ऊर्जा का प्रभाव यह होता है कि नकारात्मक शक्तियां, ईर्ष्या, द्वेष और दुर्भावनाएं व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पातीं। यह कोई चमत्कारिक या तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि मन और चेतना के स्तर पर होने वाला परिवर्तन है। जब व्यक्ति का मन सकारात्मक और स्थिर हो जाता है, तो बाहरी नकारात्मकता स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति सुखी, विजयी, दीर्घायु और संततिवान होता है। इसका तात्पर्य केवल भौतिक सुखों से नहीं है, बल्कि मानसिक संतोष और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाली सफलताओं और असफलताओं दोनों को समान भाव से स्वीकार करना सीख जाता है। यही संतुलन उसे वास्तविक सुख की अनुभूति कराता है।

रामरक्षा स्तोत्र का पाठ किसी विशेष काल या नियम की बाध्यता में नहीं बंधा है। इसे किसी भी समय, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। फिर भी यह कहा जाता है कि यदि इसका पाठ नित्य और श्रद्धा के साथ किया जाए, तो इसके प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नियमित पाठ से व्यक्ति के जीवन में एक अनुशासन आता है। मन धीरे-धीरे भटकाव से हटकर एक केंद्र की ओर बढ़ने लगता है। यही केंद्र श्रीराम का नाम है, जो साधक को स्थिरता प्रदान करता है। इस स्तोत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह व्यक्ति को कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्रीराम का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सत्य और मर्यादा का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही मार्ग अंततः कल्याणकारी होता है। जब साधक रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह अनजाने में ही इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगता है। उसका आचरण अधिक संयमित और विनम्र हो जाता है।

रामरक्षा स्तोत्र का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार और परिवेश पर भी पड़ता है। जिस घर में नियमित रूप से इसका पाठ होता है, वहां वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक माना जाता है। पारिवारिक कलह, तनाव और असंतोष धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। यह सब किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर आए परिवर्तन से संभव होता है।

अंततः रामरक्षा स्तोत्र एक ऐसी साधना है, जो मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि वास्तविक सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने भीतर श्रीराम के नाम को स्थापित कर लेता है, तो भय, संकट और अशांति स्वतः ही कमजोर पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि सदियों से रामरक्षा स्तोत्र को केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि जीवन का अदृश्य कवच माना गया है। यह कवच न केवल विपत्तियों से रक्षा करता है, बल्कि मनुष्य को साहस, धैर्य और शांति के मार्ग पर भी अग्रसर करता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में आने वाली नागरिकों की प्रस्तुतियों का सामूहिक प्रयासों से आवश्यक निवारण लाने हेतु राज्य सरकार के विभागों से अनुरोध

- किसानों के प्रति मुख्यमंत्री की विशेष संवेदनशीलता
- जूनागढ और मेहसाणा जिलों के किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तत्काल भुगतान करने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश
- कालोल नगरपालिका के सड़क-मार्ग एवं नाली के कार्यों की क्वालिटी में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिशानिर्देश
- मुख्यमंत्री के समक्ष दिसंबर 2025 के राज्य 'स्वागत' में 97 से अधिक प्रस्तुतिकर्ताओं की प्रस्तुतियां आईं

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को दिसंबर 2025 के राज्य 'स्वागत' में प्रस्तुति करने आए नागरिकों की प्रस्तुतियां प्रत्यक्ष रूप से सुनकर उनके उचित निवारण हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के विभागों एवं प्रशासन के अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया कि 'स्वागत' में आने वाली प्रस्तुतियों का निवारण सामूहिक प्रयासों से किया जाना चाहिए। हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाले 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के उपक्रम में दिसंबर 2025 का राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम बुधवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान राज्य भर से 97 से अधिक प्रस्तुतिकर्ता अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हुए। इतना ही नहीं, जिला स्वागत की 1,284 तथा तहसील स्वागत की 2,458 प्रस्तुतियों-प्रश्नों

के संदर्भ में जिला तहसील स्तर पर निवारण की कार्यवाही भी की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उनके समक्ष आई प्रस्तुतियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके उचित निवारण के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जूनागढ जिले की केशोद तहसील के एक धरती पुत्र को उसके खेत तक जाने के लिए रास्ता स्थानीय स्थिति की आवश्यक जांच कर उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए।

इसके अतिरिक्त, श्री पटेल ने कलेक्टर को सीपू योजना के अंतर्गत साबरमती सरस्वती लिंक कैनाल योजना में मेहसाणा के किसान की अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नगरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तथा नागरिक सुविधाओं के कार्यों में क्वालिटी बनी रहे, यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया तथा ऐसे कार्यों में लापरवाही या निष्क्रियता बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वापी नगर पालिका क्षेत्र में संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि में अंडरग्राउंड ड्रेनेज कनेक्शन हेतु हो रहे अवरोधों को दूर कर यह कनेक्शन तत्काल देने तथा बाबरा तहसील के प्रस्तुतिकर्ता को सरकार द्वारा आवंटित निःशुल्क आवासीय प्लॉट को गांव के नमूने में दर्ज कर स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इस राज्य 'स्वागत' में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, विशेष कार्य अधिकारी श्री धीरज पारेख एवं श्री राकेश व्यास, साथ ही संबंधित विभागों के सचिव गांधीनगर से तथा जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े ।

गुजरात के जंगलों तथा अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार सदैव कटिबद्धः वन मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया

राज्य के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में आज तक कभी खनन या व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी गई है और भविष्य में भी नहीं दी जाएगी : वन एवं पर्यावरण मंत्री

- अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का राज्य सरकार सख्ती से पालन करेगी
- 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' अंतर्गत वर्तमान वर्ष में 4,426 हेक्टेयर क्षेत्र में 86.84 लाख पौधों का रोपण किया गया
- आगामी वर्ष में भी 4,890 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं संरक्षण का कार्य किया जाएगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने बुधवार को अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और टिकाऊ विकास को लेकर राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात सरकार राज्य के वन क्षेत्रों और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुजरात के विभिन्न जिलों में फैली अरावली पर्वतमाला और उसके वन क्षेत्रों में राज्य सरकार ने आज तक कभी भी खनन की अनुमति नहीं दी है और भविष्य में भी खनन गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने जोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गुजरात सरकार अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा और संरक्षण के सभी पहलुओं का कार्यान्वयन कर रही है। इसके अनुसार, स्थानीय भूतल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले सभी भू-आकारों को 'पर्वत' के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी बचाव का रास्ता न रहे। इसके अतिरिक्त, 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले दो या अधिक पर्वतों के बीच के 500 मीटर तक के सभी क्षेत्र को भी अरावली पर्वतमाला का ही भाग माना जाएगा।

उन्होनें स्पष्ट किया कि गुजरात सरकार द्वारा राज्य के संरक्षित क्षेत्रों, इको-सेंसिटिव जोन्स, रिजर्व एरिया, वेटलैंड्स और कैम्पा (CAMPA) बुवाई साइट्स जैसे 'कोर और इनवायलेट' जोन्स में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण करना है, ताकि भावी पीढ़ियों को सुरक्षित और हरित गुजरात मिल सके। अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि यह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है और भूमिगत जल रिचार्ज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वन एवं पर्यावरण मंत्री ने 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट अंतर्गत गुजरात के साबरकांठा, अरवल्ली, बनासकांठा, मेहसाणा, महिसागर, दाहोद और पंचमहल जिलों के कुल 3,25,511 हेक्टेयर वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसमें ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 4,426 हेक्टेयर क्षेत्र में 86.84 लाख स्थानीय प्रजातियों के पौधों की बुवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त; मंत्री श्री अर्जुन मोढावाडिया ने अंत में कहा कि 150 हेक्टेयर क्षेत्र से बबूल और लेंटाना जैसी आक्रामक वनस्पतियों को हटाया गया है। आगामी वर्ष 2026-27 के दौरान इस प्रोजेक्ट अंतर्गत लगभग 4,890 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा संरक्षण का कामकाज किया जाएगा ।

रूफटॉप सोलर में गुजरात अव्वल: 5 लाख इंस्टॉलेशंस, 1,879 मेगावाट क्षमता हासिल

- रूफटॉप सोलर के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार दे रही 78,000 तक कई आकर्षक सब्सिडीज़
- मार्च 2027 तक 10 लाख आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लक्ष्य का 50 प्रतिशत समय से पहले किया पूरा
- आगामी VGRC, राजकोट में प्रदर्शित होगा गुजरात का रूफटॉप सोलर सफलता मॉडल

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर लिए हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1,879 मेगावाट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत प्राप्त यह उपलब्धि रूफटॉप सोलर को अपनाने में गुजरात की अग्रणी भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहन पहलों के तहत अब तक गुजरात में कुल मिलाकर 11 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, गुजरात ने मार्च 2027 तक 10 लाख आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी समय से पहले ही हासिल कर लिया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "वर्तमान समय सौर, पवन और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा संचालित ग्रीन ग्रोथ से परिभाषित होता है। गुजरात ने लंबे समय से इस बदलाव की तैयारी की है और आज राज्य भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विशेष रूप से, गुजरात सोलर रूफटॉप योजना में देश में अग्रणी है और सतत प्रगति के लिए मानक स्थापित कर रहा है। यह उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत संभव हुई है, जिनकी नवीकरणीय ऊर्जा और सतत

विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने गुजरात को अपने विज़न को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित और सक्षम किया है।"

रूफटॉप सोलर अपनाना हुआ अब और भी आसान, गुजरात सरकार दे रही कई आकर्षक सब्सिडीज़

रूफटॉप सोलर को व्यापक रूप से अपनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इसके तहत 2 किलोवाट तक की क्षमता वाले सिस्टम पर 30,000 प्रति किलोवाट, 2 किलोवाट से अधिक और 3 किलोवाट तक की क्षमता पर 18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 3 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। अब तक आवासीय उपभोक्ताओं को इस योजना के अंतर्गत 3,778 करोड़ की सब्सिडी का लाभ मिल चुका है।

इतना ही नहीं, राज्य में 6 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 2,950 तक नियामक शुल्क सहायता भी दी जाती है, नेटवर्क सुदृढ़ीकरण शुल्क माफ किया गया है और उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग समझौते से भी छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, आवासीय सोलर इंस्टॉलेशन के लिए कोई लोड सीमा नहीं है। साथ ही, उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली बेचने की सुविधा मिलती है और उन पर कोई बैंकिंग शुल्क भी नहीं लगाया जाता है।

आगामी VGRC, राजकोट में प्रदर्शित होगा गुजरात का रूफटॉप सोलर सफलता मॉडल

10 जनवरी से राजकोट में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात रिजनल कॉन्फ्रेंस में गुजरात रूफटॉप सोलर की प्रेरक सफलताओं कहानियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिनमें उन घरों की मिसालें होंगी जिन्होंने न केवल अपने बिजली खर्च को कम किया है बल्कि आज वे रूफ़टॉप सोलर से अतिरिक्त बिजली जनरेट कर ग्रिड को भी उपलब्ध करा रहे हैं और इससे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं।

सोना वायदा में 393 रुपये और चांदी वायदा में 3700 रुपये का ऊछालः क्रूड ऑयल वायदा 32 रुपये बढ़ा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 323471.04 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 44533.43 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 278919.16 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 34673 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2518.01 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 32992.85 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 138166 रुपये के भाव पर खूलकर, 138676 रुपये के दिन के उच्च और 138085 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 137885 रुपये के पिछले बंद के सामने 393 रुपये या 0.29 फीसदी की मजबूती के साथ 138278 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 497 रुपये या 0.45 फीसदी बढ़कर 110483 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 47 रुपये या 0.34 फीसदी बढ़कर 13810 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा 136309 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 136500 रुपये और नीचे में 136000 रुपये पर पहुंचकर, 449 रुपये या 0.33 फीसदी बढ़कर 136248 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 136671 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 136893 रुपये और नीचे में 136266 रुपये पर पहुंचकर, 136076 रुपये के पिछले बंद के सामने 576 रुपये या 0.42 फीसदी बढ़कर 136652 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 221000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 224300 रुपये और नीचे में 221000 रुपये पर पहुंचकर, 219653 रुपये के पिछले बंद के सामने 3700 रुपये या 1.68 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 223353 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 3724 रुपये या 1.69 फीसदी बढ़कर 223927 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 3675 रुपये या 1.67 फीसदी की बढ़त के साथ 223883 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

- कमोडिटी वायदाओं में 44533.43 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 278919.16 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 32992.85 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34673 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 7181.23 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 22.35 रुपये या 1.96 फीसदी की तेजी के संग 1162.2 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 1.4 रुपये या 0.46 फीसदी की मजबूती के साथ 306.15 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 2.1 रुपये या 0.74 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी चढ़कर 181.95 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4222.37 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5258 रुपये के भाव पर खूलकर, 5303 रुपये के दिन के उच्च और 5253 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 32 रुपये या 0.61 फीसदी की तेजी के संग 5286 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 34 रुपये या 0.65 फीसदी की तेजी के संग 5287 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा।

इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 396 रुपये के भाव पर खूलकर, 408.1 रुपये के दिन के उच्च और 390.4 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 380.8 रुपये के पिछले बंद के सामने 13.7 रुपये या 3.6 फीसदी की मजबूती के साथ 394.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 14.6 रुपये या 3.85 फीसदी की मजबूती के साथ 394.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 939 रुपये पर खूलकर, 60 पैसे या 0.06 फीसदी बढ़कर 941.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 13583.44 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 19409.41 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 6114.05 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 237.18 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 17.52 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 812.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 361.38 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 3849.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17352 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 82222 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 22700 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 350693 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 37357 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17300 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 43975 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 108403 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20588 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 38895 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 34702 पॉइंट पर खूलकर, 34775 के उच्च और 34603 के नीचले स्तर को छूकर, 225 पॉइंट बढ़कर 34673 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 9.2 रुपये की बढ़त के साथ 149.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.75 रुपये की बढ़त के साथ 16.45 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 42 रुपये की बढ़त के साथ 1218 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 229000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 116 रुपये की बढ़त के साथ 174.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1170 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 15.95 रुपये की बढ़त के साथ 42 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.69 रुपये की बढ़त के साथ 4.6 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 24.3 रुपये की गिरावट के साथ 168.9 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.65 रुपये की गिरावट के साथ 32.65 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 138000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 252.5 रुपये की गिरावट के साथ 1450 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 220000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2162.5 रुपये की गिरावट के साथ 408 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो बिना बदलाव के 4.58 रुपये हुआ।

वडोदरा स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर लाइन नं 3 पर इंजीनियरिंग कार्य (Complete Track Renewal) हेतु 24 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2025 तक ब्लॉक लिया गया है। जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:-

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 69108 अहमदाबाद-वडोदरा मेमू दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन बाजवा-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 69102 अहमदाबाद-वडोदरा मेमू दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन बाजवा-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

3.ट्रेन संख्या 19036 अहमदाबाद-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक बाजवा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन बाजवा-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

4.ट्रेन संख्या 12929 वलसाड -वडोदरा इंटरसिटी दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक विश्वामित्री स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन विश्वामित्री -वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

5.ट्रेन संख्या 69120 दाहोद -वडोदरा मेमू दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन छायापुरी-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

6.ट्रेन संख्या 69118 गोधरा -वडोदरा मेमू दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक छायापुरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा यह ट्रेन छायापुरी-वडोदरा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होने वाली ट्रेनें

1.ट्रेन संख्या 69107 वडोदरा-अहमदाबाद मेमू दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 19035 वडोदरा-अहमदाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक बाजवा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-बाजवा के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

3.ट्रेन संख्या 69119 वडोदरा - दाहोद मेमू दिनांक 24.12.2025 से 17.01.2026 तक छायापुरी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा वडोदरा-छायापुरी के बीच आंशिक निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करे।ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गांधीनगर में टाइप-1 डायबिटीज कार्यक्रम का राज्यव्यापी प्रारंभ

- दूरदराजी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टाइप-1 डायबिटीज के उपचार का लाभ देकर इस रोग से पीड़ित सभी बच्चों को उपचार अंतर्गत लाने का स्वास्थ्य सेवा-उन्मुखी दृष्टिकोण
- मुख्यमंत्री ने टाइप-1 डायबिटीज से पीड़ित एक भी बच्चा उपचार सुविधा से वंचित न रह जाए; ऐसी सघन व्यवस्था की मंशा व्यक्त की
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य सरकार ने प्रिकॉशन, प्रिवेंशन तथा पॉजिटिव लाइफस्टाइल पर फोकस किया है : मुख्यमंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में टाइप-1 डायबिटीज (जुवेनाइल डायबिटीज) से पीड़ित एक भी बच्चा उपचार-सुविधा से वंचित न रहे; ऐसी सघन उपचार व्यवस्था की राज्य सरकार की मंशा व्यक्त की है। श्री पटेल ने टाइप-1 डायबिटीज (जुवेनाइल डायबिटीज) उपचार-नियंत्रण कार्यक्रम का बुधवार को गांधीनगर से प्रारंभ कराते हुए यह मंशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरदराजी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में भी टाइप-1 डायबिटीज के उपचार का लाभ उपलब्ध हो और इस रोग से पीड़ित सभी बच्चों को उपचार अंतर्गत लाया जाए; ऐसे स्वास्थ्य सेवा-उन्मुखी दृष्टिकोण से हम यह राज्यव्यापी अभियान शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प किया है। इसके लिए उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति को भी श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने हेतु आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा-देखभाल योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं; लोग निरोगी रहें, इसके लिए प्रधानमंत्री ने योग के प्रचार-प्रसार को भी महत्व दिया है। इसके बावजूद अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो आयुष्मान कार्ड से सरकार उसके उपचार के लिए उसके साथ खड़ी है। योग से आयुष्मान की प्रधानमंत्री की यह विशिष्ट संकल्पना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने भी टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों के सटीक निदान एवं समय पर उपचार द्वारा इस रोग को नियंत्रित करने का संकल्प किया है।

उन्होंने राज्यव्यापी अभियान के प्रारंभ होने के अवसर पर टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों को उपचार किट का वितरण करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों के उपचार का बोझ परिवार पर न आ पड़े; इसके लिए राज्य सरकार निःशुल्क इंजेक्शन, ग्लूकोमीटर तथा अन्य आवश्यक उपचार सामग्री प्रदान करती है। श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में राज्य सरकार ने बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रिकॉशन, प्रिवेंशन तथा पॉजिटिव लाइफस्टाइल; तीनों पर फोकस किया है। राज्य के विद्यालयों में शाला स्वास्थ्य अभियान शुरू कर हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है। उन्होंने कहा कि इस जाँच के दौरान यदि किसी बच्चे को अधिक उपचार की जरूरत प्रतीत हो, तो सरकारी अस्पतालों में रीफर कर किडनी, हृदय रोग, कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट जैसा सुपर स्पेशलिस्ट उपचार राज्य सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराती है। पिछले 11 वर्षों में 2 लाख 18 हजार से अधिक बच्चों को इस तरह का उपचार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की लाइफस्टाइल तथा स्ट्रेसफुल जीवनशैली के कारण वयस्क एवं युवावस्था में भी डायबिटीज की व्यापकता बढ़ रही है। जीवनशैली में बदलाव लाकर उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में बढ़ती जा रही मेदस्विता को लेकर लोगों को सावधान होने के लिए भोजन में तेल का उपयोग 10 प्रतिशत घटाने और नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सभी से इस अपील को अपनाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत@2047 के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संकल्प को स्वस्थ एवं समृद्ध विकसित गुजरात से साकार करने का भी आह्वान किया। इस राज्यव्यापी अभियान के प्रारंभ अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. आशित दवे, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री अनिलभाई पटेल, जिला-शहर के पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री धनंजय द्विवेदी, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य आयुक्त श्री हर्षद पटेल व डॉ. रतनकँवर गढवी चारण, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, बच्चे और उनके परिजन उपस्थित रहे।

विकास को मिली नई रफ्तार, केंद्र सरकार का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान देश की तस्वीर बदलेगा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 12.35 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बल्कि पूरे देश में परिवहन, आवास, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की नींव रखेंगी। इन फैसलों को सरकार के दीर्घकालिक विकास विजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में दिल्ली मेट्रो फेज-5 (A) के विस्तार को मंजूरी देना शामिल है। दिल्ली और एनसीआर की जीवनरेखा मानी जाने वाली मेट्रो के इस नए चरण के लिए केंद्र सरकार ने 12,015 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। इस परियोजना से राजधानी और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से जहां एक ओर यातायात का दबाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण घटाने और समय की बचत करने में भी यह अहम भूमिका निभाएगा। सरकार का मानना है कि मजबूत और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ही शहरी विकास की रीढ़ होती है, और दिल्ली मेट्रो इस दिशा में देश का सबसे सफल मॉडल बनकर उभरी है।

केंद्र सरकार ने केवल मेट्रो ही नहीं, बल्कि देश के संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, आवास और ऊर्जा क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने हाईवे सेक्टर के लिए रिकॉर्ड 1,97,644 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके तहत 8 नेशनल हाई-स्पीड रोड प्रोजेक्ट्स, जिनकी कुल लंबाई लगभग 936 किलोमीटर होगी, को आगे बढ़ाया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और दूरदराज तथा सीमावर्ती इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना भी है।

सरकार ने पूर्वोत्तर भारत, सीमावर्ती क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों पर विशेष फोकस किया है। शिलॉन्ग से सिलचर तक बेहतर कनेक्टिविटी, बिहार में पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर और दक्षिण भारत में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयास इसी रणनीति का हिस्सा हैं। सरकार का मानना है कि सड़क नेटवर्क के मजबूत होने से न केवल व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन, रोजगार और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

रेलवे क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निवेश करने का फैसला किया है। लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और माल व यात्री परिवहन को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से रेलवे के 43 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 1,52,583 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण होगा, नई लाइनें बिछेंगी और क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार का दावा है कि इससे उद्योगों को तेज और सस्ता परिवहन मिलेगा, जिससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी।

पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर को भी केंद्र सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे नहीं छोड़ा है। इस क्षेत्र के लिए 1,45,945 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र का वधावन पोर्ट एक प्रमुख परियोजना है। वधावन पोर्ट को भविष्य के सबसे बड़े और आधुनिक बंदरगाहों में से एक के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे भारत की समुद्री व्यापार क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और देश वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकेगा।

हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। बागडोगरा, बिहटा, वाराणसी और कोटा समेत कई शहरों में नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स के निर्माण और विस्तार के लिए 7,339 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे छोटे और मझोले शहरों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। शहरी परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के साथ-साथ बेंगलुरु मेट्रो के दो कॉरिडोर, ठाणे रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और लखनऊ मेट्रो से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 1,31,542 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेट्रो और अन्य मास ट्रांजिट सिस्टम को तेजी से विकसित किया जाए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 28,602 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन स्मार्ट सिटीज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लॉजिस्टिक्स और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा, जिससे देश और विदेश से निवेश आकर्षित हो सके। इसके साथ ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

आवास क्षेत्र में भी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी और दो करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए 5,36,137 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इससे करोड़ों लोगों का पक्का घर पाने का सपना साकार होगा और सामाजिक समानता को मजबूती मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में 28,432 करोड़ रुपये की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, जिससे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र तीर्थस्थलों के लिए रोपवे परियोजनाओं को भी 6,811 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी।

कुल मिलाकर, एक ही बैठक में 12.35 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शहरीकरण और जीवन स्तर पर साफ दिखाई देगा। सरकार का यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की भारत की तस्वीर को भी नए सिरे से गढ़ने का काम करेगा।

रेल पटरियों पर अब तकनीक का पहरा, वन्यजीवों की मौत रोकने के लिए एआई से लैस होगा रेलवे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। असम में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आकर सात हाथियों की दर्दनाक मौत के बाद भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। बार-बार हो रही वन्यजीवों की मौतों और इससे पैदा हो रहे खतरे को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन अब पारंपरिक निगरानी से आगे बढ़कर अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। आने वाले समय में रेलवे ट्रैक पर एआई आधारित सिस्टम तैनात किया जाएगा, जो हाथी, बाघ, शेर जैसे बड़े वन्यजीवों की मौजूदगी को पहले ही पहचान कर अलर्ट जारी करेगा, ताकि समय रहते ट्रेन की गति रोकी या नियंत्रित की जा सके और जान-माल की हानि को टाला जा सके।

कुछ दिन पहले असम के होजाई जिले में सैरांग से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई थी। जंगल क्षेत्र से गुजरते वक्त रेलवे ट्रैक पार कर रहे हाथियों के झुंड से ट्रेन की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन का इंजन और पांच कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में सात हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक हाथी गंभीर रूप से घायल हुआ। गनीमत रही कि ट्रेन में सवार यात्रियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने रेलवे और वन विभाग दोनों की चिंताओं को बढ़ा दिया। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि देश के कई हिस्सों में रेलवे लाइनें वन्यजीवों के प्राकृतिक गलियारों से होकर गुजरती हैं, जहां टकराव का खतरा लगातार बना रहता है।

रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हर साल कई वन्यजीव ट्रेन की चपेट में आकर मारे जाते हैं। इनमें हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। हाथी झुंड में चलते हैं और अक्सर रात के समय या घने जंगलों में ट्रैक पार करते हैं, जहां ड्राइवर को समय पर उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि तमाम चेतावनियों, स्पीड प्रतिबंधों और मैनुअल निगरानी के बावजूद हादसे पूरी तरह रुक नहीं पा रहे थे। असम की घटना ने रेलवे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब तकनीक के बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अब ट्रैक पर एआई आधारित इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है, जो डिस्ट्रिब्यूटेड एकॉस्टिक सिस्टम तकनीक पर काम करता है। यह सिस्टम ट्रैक के किनारे बिछाए गए फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए आसपास होने वाली हलचल, कंपन और आवाज़ों को पकड़ता है। एआई एल्गोरिदम इन संकेतों का विश्लेषण कर यह पहचान लेता है कि कोई बड़ा जानवर ट्रैक के पास आ रहा है या ट्रैक पार करने वाला है। जैसे ही सिस्टम को हाथी या किसी अन्य बड़े वन्यजीव की मौजूदगी का संकेत मिलता है, वह तुरंत कंट्रोल रूम, स्टेशन मास्टर और लोको पायलट को अलर्ट भेज देता है। इस तकनीक की सबसे अहम बात यह है कि ट्रेन चालक को करीब 500 मीटर पहले ही चेतावनी मिल जाती है। इससे लोको पायलट के पास पर्याप्त समय होता है कि वह ट्रेन की रफ्तार कम कर सके या जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रोक सके। रेलवे का कहना है कि शुरुआती परीक्षणों में यह सिस्टम काफी सटीक साबित हुआ है और गलत अलर्ट की संभावना बेहद कम पाई गई है। यही वजह है कि अब इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का फैसला लिया गया है।

फिलहाल यह एआई सिस्टम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के 141 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लगाया गया है, जहां हाथियों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों के दौरान सिस्टम ने कई बार समय रहते चेतावनी देकर संभावित हादसों को टालने में मदद की है। सकारात्मक नतीजों से उत्साहित रेलवे ने अब इसे देशभर में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 981 किलोमीटर नए ट्रैक पर इस सिस्टम को लगाने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। आने वाले चरणों में इसे उन सभी रूट्स पर लगाया जाएगा, जो जंगलों और वन्यजीव गलियारों से होकर गुजरते हैं।

रेलवे का मानना है कि यह कदम सिर्फ वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। जब कोई ट्रेन किसी बड़े जानवर से टकराती है, तो न सिर्फ जानवर की मौत होती है, बल्कि ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा भी रहता है, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है।

केरल में मतदाता सूची की शुद्धता पर सख्त निगरानी, एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने तैनात किए वरिष्ठ ऑब्जर्वर

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। वर्ष 2026 में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए केरल में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर ने बुधवार को जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने पूरे केरल में चुनावी रोल के 'विशेष गहन संशोधन' यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की निगरानी के लिए चार वरिष्ठ चुनावी रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। इन ऑब्जर्वरों को राज्य के सभी 14 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी, फर्जीवाड़े या चूक को समय रहते पकड़ा जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, एसआईआर की प्रक्रिया चुनावी व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होता है कि कौन मतदाता वोट डालने का अधिकार रखता है। बीते कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर विवाद सामने आए हैं। इन्हीं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार विशेष सतर्कता बरतने का फैसला किया है। केरल जैसे राज्य में, जहां साक्षरता दर ऊंची है और राजनीतिक जागरूकता भी काफी मजबूत मानी जाती है, वहां मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखना आयोग के लिए प्राथमिकता बन गई है। चुनाव आयोग द्वारा जिन चार वरिष्ठ अधिकारियों को ईआरओ यानी चुनावी रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनमें एम. जी. राजामणिक्यम, के. बीजू, टिंकू बिस्वाल और के. वासुकी शामिल हैं। ये सभी अनुभवी नौकरशाह माने जाते हैं और प्रशासनिक व चुनावी प्रक्रियाओं का लंबा अनुभव रखते हैं। आयोग ने जिलों का बंटवारा इस तरह किया है कि हर ऑब्जर्वर को भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से संतुलित जिम्मेदारी मिले। एम. जी. राजामणिक्यम को कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जो राज्य के उत्तरी हिस्से में आते हैं और जहां आदिवासी क्षेत्रों से लेकर तटीय इलाकों तक मतदाता संरचना काफी विविध है। के. बीजू को त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम जिलों का प्रभारी बनाया गया है, जो केरल के मध्य हिस्से में स्थित हैं और जहां शहरी व ग्रामीण मतदाताओं का संतुलन देखने को मिलता है। टिंकू बिस्वाल को कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों की निगरानी सौंपी गई है, जबकि के. वासुकी को राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के साथ कोल्लम, पठानमथिट्टा और अलाप्पुझा जिलों का जिम्मा दिया गया है।

हावड़ा में बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या पर उबाल, भाजपा प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ंत

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बुधवार को उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए, जब बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की नृशंस हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते यह प्रदर्शन पुलिस के साथ टकराव में बदल गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, भाजपा कार्यकर्ता हावड़ा ब्रिज की ओर मार्च करते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताना चाहते थे। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और पार्टी के झंडे लिए नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर जैसे ही प्रदर्शनकारियों को रोका गया, माहौल गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।

पुलिस के रोकने के बाद भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और धरना देने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश भी की, जिससे हालात और बिगड़ गए। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए सख्ती दिखानी पड़ी। झड़प के चलते कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हाल में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जा सकता और प्रदर्शन के नाम पर आम नागरिकों की आवाजाही रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हावड़ा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को पहले ही वैकल्पिक स्थान पर विरोध जताने की अनुमति देने की बात कही गई थी, लेकिन जब उन्होंने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अधिकारी के मुताबिक, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

इस विरोध प्रदर्शन की वजह 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के बालुका इलाके में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना है। आरोप है कि 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को जला दिए जाने की बात भी सामने आई है। इस घटना ने बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि भारत में भी व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है।

भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। पार्टी का कहना है कि दीपू चंद्र दास की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा का प्रतीक है। इसी के विरोध में हावड़ा सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की, ताकि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं, पुलिस के साथ हुई झड़प को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया।

घटना के बाद हावड़ा इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल सतर्क हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत में उस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया को लेकर बहस को तेज कर दिया है।

सीसीटीवी से सुराग, सीमा पार तक पीछा: 60 लाख की मोबाइल चोरी का पर्दाफाश

(जीएनएस)। कानपुर। गोविंदनगर थाना क्षेत्र में हुए मोबाइल शोरूम चोरी कांड ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, लेकिन सतर्क जांच, तकनीकी विश्लेषण और लगातार दबिशों के बाद आखिरकार इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के पांच शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपये कीमत के 113 महंगे स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इस गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने देर रात प्रेस वार्ता में बताया कि सात दिसंबर की रात गोविंदनगर स्थित कृष्णा मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। शोरूम का शटर तोड़कर भीतर दाखिल हुए बदमाशों ने बड़ी सफाई से कीमती मोबाइल फोन समेट लिए और कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक नीरज बलेचा को घटना की जानकारी मिली, तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही गोविंदनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई।

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पुलिस के लिए अहम सुराग दिए। फुटेज में साफ दिखा कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे और चोरी के दौरान किसी तरह का शोर न हो, इसका भी ध्यान रखा गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की गतिविधियों, उनके आने-जाने के रास्तों और समय का बारीकी से विश्लेषण किया। इसके बाद पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तीन विशेष टीमें गठित की गईं, जिन्हें अलग-अलग दिशाओं में जांच के लिए रवाना किया गया।

करीब 17 दिनों तक चली इस जांच में पुलिस ने कानपुर के अलावा लखनऊ, बिहार और नेपाल तक छानबीन की। इस दौरान लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज के सहारे आरोपियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया और धीरे-धीरे पुलिस इस अंतरराज्यीय गिरोह तक पहुंचने में सफल हुई। लगातार दबिशों के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन निवासी मुबीन, प्रमोद पासवान और मुकेश, नेपाल के परसा निवासी कृष्णा तथा कानपुर के बजरिया क्षेत्र निवासी शोएब के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से संगठित तरीके से शोरूम चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। उनका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और चोरी का अधिकांश माल नेपाल में खपाया जाता था, जहां इनकी अच्छी पकड़ थी।

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे बड़े शहरों को खासतौर पर निशाना बनाते थे, जहां महंगे मोबाइल, लैपटॉप और ब्रांडेड घड़ियों के शोरूम होते हैं। मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, लखनऊ और अयोध्या जैसे शहरों में भी इस गिरोह ने पहले कई वारदातों को अंजाम दिया है। चोरी के बाद माल को तुरंत अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था, ताकि किसी एक जगह से पूरा माल बरामद न हो सके। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चोरी का माल खपाने के लिए इनके पास स्थानीय संपर्क भी मौजूद थे।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि बिहार के घोड़ासहन गांव में दबिश के दौरान एक गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हुई, जब स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने संयम और सतर्कता से स्थिति को संभाला और अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस घटना को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है और संबंधित लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बरामद किए गए 113 स्मार्टफोन की कीमत लगभग 60 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, यह पूरा माल शोरूम से चोरी किया गया था और इसे बेचने की तैयारी चल रही थी। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि फरार आरोपी असलम की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस बड़ी सफलता पर पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त की ओर से खुलासा करने वाली टीम को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुलिस आयुक्त ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्रवाई न केवल कानपुर, बल्कि पूरे क्षेत्र में संगठित अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है। उन्होंने कहा कि तकनीक, मेहनत और समन्वय के बल पर अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मोबाइल शोरूम चोरी कांड के खुलासे से जहां व्यापारियों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस की सक्रियता और तत्परता की भी सराहना हो रही है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि संगठित अपराध चाहे जितना शातिर क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ अंततः उसे पकड़ ही लेते हैं।

घर खरीदने की चाहत को नई उड़ान, सस्ती हुई होम लोन की राह

(जीएनएस)। नई दिल्ली। अपने घर का सपना हर मध्यमवर्गीय परिवार के जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक होता है। वर्षों की बचत, भविष्य की योजनाएं और एक सुरक्षित छत की उम्मीद इसी सपने से जुड़ी होती है। ऐसे में जब भी होम लोन की ब्याज दरों में कमी की खबर आती है, तो यह लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इसी कड़ी में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है, जिससे अब नए होम लोन पर ब्याज दर 7.15 प्रतिशत से शुरू होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब महंगाई, बढ़ती जीवन-यापन लागत और रियल एस्टेट की ऊंची कीमतों के बीच आम आदमी अपने घर का सपना पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का कहना है कि यह नई ब्याज दरें ग्राहकों के सिबिल स्कोर पर आधारित होंगी। यानी जिन लोगों का क्रेडिट रिकॉर्ड मजबूत है, उन्हें सबसे अधिक फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी नई जान फूंक सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण कई लोग घर खरीदने का फैसला टालते रहे थे। अब कम ब्याज दरों के चलते फिर से मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में रेपो रेट में की गई कटौती का सीधा असर है। जब केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में नरमी दिखाता है, तो इसका लाभ धीरे-धीरे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने साफ किया है कि नई दरें सिर्फ नए ग्राहकों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे जो अपना पुराना होम लोन किसी दूसरी संस्था से ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इससे मौजूदा कर्जदारों को भी अपनी मासिक किस्त यानी ईएमआई कम कराने का अवसर मिलेगा।

कंपनी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 825 या उससे अधिक है, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ग्राहक 5 करोड़ रुपये तक के होम लोन पर केवल 7.15 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे। वहीं, यदि लोन की राशि 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपये के बीच है, तो ब्याज दर 7.45 प्रतिशत तय की गई है। यह दरें मौजूदा बाजार स्थितियों में काफी प्रतिस्पर्धी मानी जा रही हैं। इसका उद्देश्य उन ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, जिन्होंने समय पर भुगतान कर अपना क्रेडिट रिकॉर्ड मजबूत रखा है।

अगर किसी ग्राहक का सिबिल स्कोर 800 से 824 के बीच है, तो भी उन्हें राहत मिलेगी। इस श्रेणी में 5 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज दर 7.25 प्रतिशत और 5 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक के लोन पर 7.55 प्रतिशत रखी गई है। यह दरें उन लोगों के लिए आकर्षक हैं, जो बड़े शहरों में फ्लैट या स्वतंत्र मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, जहां संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

मध्यम सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों के लिए भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने दरवाजे खुले रखे हैं। जिनका स्कोर 775 से 799 के बीच है, उन्हें भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस श्रेणी में 50 लाख रुपये तक के लोन पर 7.35 प्रतिशत, 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 7.45 प्रतिशत और 2 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक के लोन पर 7.65 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह उन परिवारों के लिए राहत की खबर है, जो महानगरों या उभरते शहरों में मध्यम बजट के घर खरीदने की योजना बना रहे हैं।

वहीं जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 775 से 600 के बीच है, उनके लिए ब्याज दरें थोड़ी अधिक जरूर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें बाजार के अन्य विकल्पों की तुलना में संतुलित माना जा रहा है। इस श्रेणी में 50 लाख रुपये तक के लोन पर 7.35 से 8.75 प्रतिशत, 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 7.45 से 8.85 प्रतिशत और 2 करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक के लोन पर 7.65 से 9.50 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ग के ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर में सुधार पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें और सस्ती दरों पर लोन मिल सके।

कम सिबिल स्कोर वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दरें अपेक्षाकृत ज्यादा रखी गई हैं। जिनका सिबिल स्कोर 600 से कम है, उन्हें 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर 9.55 प्रतिशत, 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक 9.65 प्रतिशत और 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के लोन पर 10 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा। यह दरें यह संकेत देती हैं कि वित्तीय अनुशासन और समय पर भुगतान कितना जरूरी है। कमजोर क्रेडिट इतिहास वाले ग्राहकों के लिए यह एक चेतावनी भी है कि भविष्य में सस्ते कर्ज का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपनी वित्तीय आदतों में सुधार करना होगा।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने कम लोन राशि लेने वालों के लिए भी राहत की व्यवस्था की है। जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर 100 से 150 के बीच है, वे अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का होम लोन ले सकते हैं। इस श्रेणी में 35 लाख रुपये तक के लोन पर 7.65 से 7.95 प्रतिशत और 35 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर 7.75 से 8.05 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी। यह उन लोगों के लिए खास है, जो छोटे शहरों या कस्बों में सीमित बजट में घर बनाने या खरीदने की सोच रहे हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की नई ब्याज दरें कई मामलों में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी कम हैं। एसबीआई फिलहाल 7.25 प्रतिशत की शुरुआती दर पर होम लोन दे रहा है, जबकि उसकी सामान्य दरें 7.25 से 8.45 प्रतिशत के बीच हैं। ऐसे में जिन ग्राहकों का सिबिल स्कोर अच्छा है, उनके लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ऑफर ज्यादा आकर्षक बनकर सामने आया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों में यह कटौती न केवल ग्राहकों की मासिक किस्त को कम करेगी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी गति देगी। इससे निर्माण कार्य, रोजगार और उससे जुड़े अन्य उद्योगों को भी फायदा होगा। कुल मिलाकर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का यह कदम उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है, जो वर्षों से अपने घर के सपने को साकार करने का इंतजार कर रहे थे। सस्ती दरों पर होम लोन उपलब्ध होने से अब 'अपना घर' केवल सपना नहीं, बल्कि एक सुलभ हकीकत बनता नजर आ रहा है।